आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून उत्तराखण्ड)
बुधवार 25.06.2025
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा– आज का युवा आपातकाल के अंधकारमय कालखंड से अनभिज्ञ नहीं रह सकता।
- लोकतंत्र को बचाने के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में संविधान हत्या दिवस मनाया गया।
- राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
- उत्तराखंड उच्च न्यायायल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण की अगली सुनवाई कल भी जारी रखी।

उपराष्ट्रपति / कुमाऊं विश्वविद्यालय

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पचास वर्ष पहले, इसी दिन, विश्व का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और अब सबसे जीवंत लोकतंत्र एक गंभीर संकट से गुज़रा। यह था आपातकाल का थोपना। श्री धनखड़ आज कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, में स्वर्ण जयंती समारोह में छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड ने कहा कि उस समय की प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र की उपेक्षा कर व्यक्तिगत हित के लिए निर्णय लिया। राष्ट्रपति ने संवैधानिक मूल्यों को कुचलते हुए आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद जो 21 महीनों का कालखंड आया, वह लोकतंत्र के लिए अत्यंत अशांत और अकल्पनीय था। संविधान हत्या दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को इस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जब तक वे इसके बारे में जानेंगे नहीं, तो समझेंगे नहीं। उप राष्ट्रपति ने कहा कि यही कारण है कि युवाओं को जागरूक बनाना ज़रूरी है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे लोकतंत्र और शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भागीदार हैं और इस बात को भूल नहीं सकते और न ही इस अंधकारमय कालखंड से अनभिज्ञ रह सकते हैं। बहुत सोच–समझकर, आज की सरकार ने तय किया कि इस दिन को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। यह एक ऐसा उत्सव होगा जो सुनिश्चित करेगा कि ऐसा फिर कभी न हो। यह उन दोषियों की पहचान का भी अवसर होगा जिन्होंने मानवीय अधिकारों, संविधान की आत्मा और भाव को कुचला।

संविधान हत्या दिवस

आज संविधान हत्या दिवस है। यह दिन हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है, जब 25 जून, 1975 को संविधान का गला घोंटकर देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। यह आपातकाल से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के पचास साल पूरे हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन, भारतीय संविधान में निहित मूल्यों, मौलिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया।

मुख्यमंत्री / लोकतंत्र सेनानी

संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोकतंत्र सेनानियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1975 में सत्ता की भूख में अंधी कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलते हुए पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई, प्रेस की आज़ादी पर ताले जड़ दिए गए और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बलपूर्वक समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, संविधान की खुलेआम हत्या थी। उन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अत्याचार का डटकर विरोध करने वाले सभी लोकतंत्र के प्रहरियों को नमन करते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस के कारण भारत आज भी एक जीवंत लोकतंत्र है। उधर, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर चम्पावत जिले में इसे काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन कर आपातकाल के दौरान प्रताड़ित हुए लोगों के परिजनों को सम्मानित किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने किया। वक्ताओं ने 25 जून 1975 को आपातकाल के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं का जिक्र कर इसे अमानवीय व लोकतंत्र की हत्या बताया।

स्मार्ट मीटर चमोली

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी के शासकीय आवास में स्मार्ट बिजली मीटर लगाया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि इसी तर्ज पर जिले के सभी शासकीय आवासों और कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने आमजन से भी स्मार्ट मीटर लगाने की अपील की है, ताकि पारंपरिक मीटरिंग प्रणाली से हटकर एक आधुनिक, सटीक और जिम्मेदार विद्युत उपभोग की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां स्मार्ट मीटर से बिजली के बिलों में पारदर्शिता आएगी, वहीं उपभोक्ता अपनी विद्युत खपत का आकलन कर सकेंगे, जिससे ऊर्जा की अनावश्यक बर्बादी को रोका जा सकेगा।

गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता अपनी विद्युत खपत की रियल टाइम निगरानी कर सकेंगे, जिससे विद्युत उपभोग में पारदर्शिता के साथ ही ऊर्जा बचत भी सुनिश्चित होगी।

राज्य मंत्रिमंडल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों के सृजन के लिए 'उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली–2025' को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के शुरू होने की दशा में और इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया। पंचम विधानसभा के 2025 के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र के लिए स्थान और तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। पंचायती राज विभाग से संबंधित एकल सदस्य समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट का अध्ययन कर मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया।

चुनाव प्रक्रिया रोक जारी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई कल 26 जून को भी जारी रखी है। आज मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ में बहस हुई। जिसमें सरकार की ओर से महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना एकमात्र विकल्प था।

जबकि याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम व संविधान के अनुच्छेद व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है। यह संवैधानिक बाध्यता है। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने इन याचिकाओं की सुनवाई कल भी जारी रखी है।

भारतीय संरक्षण सम्मेलन

देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में आज भारतीय संरक्षण सम्मेलन–2025 की शुरुआत हुई। यह सम्मेलन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बिलाल हबीब ने बताया कि तीन दिवसीय इस सम्मेलन में देश–विदेश से 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक शोध, नीति निर्माण और सामुदायिक भागीदारी को एक मंच पर लाना है। सम्मेलन के जरिए सभी के अनुभवों को साझा कर भविष्य की रणनीति को तैयार की जाएगी।

बीआईएस चौपाल उत्तरकाशी

भारतीय मानक ब्यूरो– बीआईएस देहरादून शाखा कार्यालय की ओर से उत्तरकाशी जिले में मुखवा और पुजार गांव में दो दिवसीय मानक चौपाल कार्यक्रम सम्पन्न हो गया। पुजार गांव के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित मानक चौपाल की अध्यक्षता गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान ने की। इस अवसर पर उन्होंने बीआईएस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहलों से ग्रामीण जनजीवन में गुणवत्तापूर्ण सोच और उत्पादों के प्रति जागरूकता आती है। वहीं, मुखवा गांव में आयोजित चौपाल में स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। दोनों चौपालों में 220 से अधिक ग्रामीणों को बीआईएस के मानकों, आईएसआई चिन्हित उत्पादों, हॉलमार्किंग और उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित जानकारी दी गई। बीआईएस के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए सही उत्पादों की पहचान और उनका चयन अत्यंत आवश्यक है, जिसमें बीआईएस द्वारा विकसित मानक उपभोक्ताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं।